

- भारत की जनसांख्यिकीय और आर्थिक क्षमता: 30 वर्ष से कम आयु वाली जनसंख्या 50% से अधिक होने और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) लगभग 30% से कम होने के कारण, भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल अपरयुक्त बाज़ार प्रदान करता है।
 - बढ़ती आय, वसितारशील मध्यम वर्ग, अंगरेज़ी भाषा में दक्षता और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के प्रति बढ़ती आकांक्षाएँ भारत को विदेशी विश्वविद्यालयों के लिये एक आकर्षक गंतव्य बनाती हैं।
- विविधीकरण की वैश्विक पर्यास: बरटिन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के विश्वविद्यालयों में, जहाँ कुल नामांकन में लगभग

- एक-तहियाँ अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं, घरेलू नामांकन में ठहराव और सार्वजनिक वित्त पोषण में कमी का सामना कर रहे हैं।
- हाल ही में वीजा प्रतर्बिधों और नामांकन सीमाओं ने इन देशों के शैक्षणिक संस्थानों को भारत जैसे नए और उच्च संभावनाओं वाले बाजारों की ओर रुख करने के लिये प्रेरित किया है, ताकि वे अपनी विकास दर को बनाए रख सकें।
 - राजस्व विविधीकरण और वैश्विक उपस्थिति: भारत में परसिरो की स्थापना (जैसे कि GIFT सिटी, नवी मुंबई) विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाने, आउटबाउंड गतिशीलता पर निर्भरता कम करने और वैश्विक दृश्यता का विस्तार करते हुए सस्ती अंतरराष्ट्रीय डिग्री प्रदान करने की अनुमति देती है।
 - भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग: भारत पहले से ही वैश्विक स्तर पर रैंक प्राप्त संस्थानों (जैसे कि IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय) का केंद्र है।
 - विदेशी विश्वविद्यालय इन कॉलेजों के साथ साझेदारी कर संयुक्त परसिर स्थापित कर सकते हैं, जिससे उन्हें नई आधारभूत संरचना बनाने के बजाय मौजूदा संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिला। यह मॉडल तेजी से प्रवेश, कम निवेश सुनिश्चित करता है और शैक्षणिक सहयोग को सशक्त बनाता है।
 - उदाहरण: डीकनि विश्वविद्यालय (ऑस्ट्रेलिया) ने GIFT सिटी में अपना परसिर शुरू करने से पहले IIM बेंगलुरु के साथ साझेदारी की है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत को क्या लाभ होंगे?

- वैश्विक शिक्षा तक पहुँच: विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्रियाँ और अनुभवी संकाय प्रदान करते हैं।
 - यह छात्रों को उच्च लागत, वीजा संबंधी कठिनाइयों और जीवन-यापन व्यय के बोझ के बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे शिक्षा की वहनीयता और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।
- ब्रेन ड्रेन और विदेशी मुद्रा प्रतर्धारण: भारत में विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2019 में 5.8 लाख से बढ़कर वर्ष 2023 में 9 लाख हो गई, जिनमें से 75% से अधिक विदेश में ही रहने की इच्छा रखते हैं।
 - घरेलू विदेशी परसिरो (Domestic foreign campuses) के माध्यम से देश में ही समान शैक्षणिक गुणवत्ता उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे प्रतर्भा देश में बनी रहती है और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के बहिरगमन को रोका जा सकता है।
- अनुसंधान और शैक्षणिक सुधार: विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग से संयुक्त अनुसंधान केंद्र, संकाय आदान-प्रदान और शासन सुधारों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) में शैक्षणिक स्तर सुधरता है, अनुसंधान उत्पादन बढ़ता है तथा नवाचार व उत्कृष्टता को मजबूती मिलती है।
- उद्योग कौशल और रोजगार योग्यता: विदेशी विश्वविद्यालय उद्योगोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनमें व्यावहारिक शिक्षण, इंटरनशिप और उद्यमिता पर विशेष जोर होता है। यह कौशल अंतर को कम करने में सहायता करता है और भारतीय स्नातकों की घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में रोजगार योग्यता को बढ़ाता है।
- पारस्परिक सुविधा और रणनीतिक कूटनीति: भारत पारस्परिक सुविधा के तहत समझौता कर सकता है, जिसके अंतर्गत वह भूमि, नियामकीय समर्थन और बुनियादी ढाँचा सहायता प्रदान कर सकता है, बदले में विदेशी विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा रखी जा सकती है कि वे भारतीय संस्थानों को खाड़ी देशों और यूरोप में अपने परसिर स्थापित करने में सहयोग दें।
 - यह शैक्षणिक कूटनीति को बढ़ावा देगा, भारतीय उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करेगा और भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करेगा।
- भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना: 30 वर्ष से कम आयु की 52% जनसंख्या, तकनीकी रूप से दक्ष और अंग्रेजी बोलने वाले युवा वर्ग तथा सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थितियों के साथ, भारत एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बनने की दशा में सशक्त रूप से सक्षम है।
 - विदेशी परसिरो की मेजबानी करना सीमापार शिक्षा को बढ़ावा देता है, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व से छात्रों को आकर्षित करता है, भारत की वैश्विक शैक्षणिक उपस्थिति को मजबूत करता है और AIIMS, IIM व IIT जैसे शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतर्स्पर्द्धा को प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत के अपने 'आईवी लीग (Ivy League)' का मार्ग प्रशस्त होता है।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परसिरो से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- वहनीयता और समानता: विदेशी शाखा परसिरो में शिक्षा शुल्क अत्यधिक हो सकता है, जिससे ये मुख्य रूप से केवल समृद्ध वर्ग के लिये ही सुलभ रह जाते हैं।
 - इससे उच्च शिक्षा में सामाजिक-आर्थिक असमानता बढ़ने का खतरा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतर्भाशाली छात्र वंचित हो सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समावेशी पहुँच के NEP 2020 के लक्ष्य को नुकसान पहुँचेगा।
- सीमिति अल्पकालिक प्रणालीगत प्रभाव: यद्यपि विदेशी विश्वविद्यालय सुधार हेतु एक बड़ा कदम है, लेकिन निकट भविष्य में सीमिति छात्रों वाले केवल कुछ ही परसिर खुलेंगे।
 - इसलिये सकल नामांकन अनुपात (GER) और समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार पर उनका प्रभाव छोटा और क्रमिक होगा।
- व्यावसायीकरण एवं स्थिरता संबंधी चुनौतियाँ: विदेशी संस्थान अकादमिक अखंडता की तुलना में लाभ को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा का बाजारीकरण हो सकता है तथा मजबूत विनियमन के बिना गुणवत्ता में कमी आ सकती है।
 - चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया और खाड़ी देशों के अनुभव बताते हैं कि कम नामांकन, उच्च लागत और स्थानीय असंतुलन के कारण अक्सर परसिर बंद हो जाते हैं।
- विनियामक और बुनियादी ढाँचे संबंधी बाधाएँ: UGC (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परसिरो की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 जैसे सक्षम ढाँचे के बावजूद, विदेशी विश्वविद्यालयों को अभी भी भूमि अधिग्रहण, कराधान, श्रम कानूनों और सामान्य क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की तैयारी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

- हालाँकि GIFT सर्टि जैसे नरिदषिट क्षेत्रों में, जो वनियामक छूट और अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान करते हैं, ये बाधाएँ काफी कम हो जाती हैं ।
- सांस्कृतिक और शैक्षणिक वयोग: वदिशी विश्वविद्यालयों को भारत के सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुकूल ढलने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ।
 - प्रासंगिक पाठ्यक्रम, भारतीय संकाय और स्थानीय संस्थाओं के साथ सहयोग के माध्यम से प्रभावी स्थानीय एकीकरण के बनिा, उनके अभिजात्य, पृथक परसिर बनने का खतरा है, जो भारत के शैक्षणिक पारस्थितिकी तंत्र और सामाजिक आवश्यकताओं से अलग हो जाएंगे ।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: [भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रमुख मुद्दे](#)

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: [भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना](#)

भारत में वदिशी विश्वविद्यालयों के साथ सतत् सहयोग के लिये क्या रणनीति होनी चाहिये?

- समावेशी पहुँच सुनिश्चित करना: NEP 2020 के साथ संरेखित करने के लिये वनियमों में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति और सकारात्मक समावेशन उपायों को अनिवार्य करना चाहिये ।
 - वदिशी परसिरों में व्यापक पहुँच को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिये सरकार या संस्थानों से वित्तीय सहायता आवश्यक है ।
- लचीला लेकनि जवाबदेह शासन: एक स्तरीकृत और वभिदति नयामक मॉडल को शीर्ष रैंक वाले वैश्विक संस्थानों को परिचालन में आसानी प्रदान करनी चाहिये, साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता, वित्तीय पारदर्शिता और नैतिक आचरण पर सख्त नगिरानी सुनिश्चित करनी चाहिये ।
 - वदिशी विश्वविद्यालयों को भारतीय कानूनों, छात्र अधिकारों और शोषण-वरोधी मानदंडों के प्रतजिवाबदेह रहना चाहिये ।
- सहयोगात्मक अनुसंधान एवं कषमता नरिमाण: वदिशी विश्वविद्यालयों को भारतीय संस्थानों के साथ साझा परसिर, समझौता ज्ञापन (MoU), संयुक्त अनुसंधान केंद्र और संकाय विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिये । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को नवाचार, कषमता नरिमाण और पारस्परिक अधगम को बढ़ावा देने के लिये ऐसे सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये ।
 - सरकार को भारतीय-वदिशी शैक्षणिक सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये, जिसमें भारतीय संस्थान अवसंरचनात्मक सहयोग प्रदान करें और वैश्विक पहचान प्राप्त करें, साथ ही वदिशी पाठ्यक्रमों का भारतीयकरण (Indianisation) सुनिश्चित किया जाए ।
 - दीर्घकालिक दृष्टि से, भारत को आईवी लीग जैसी अपनी वैश्विक संस्थाएँ विकसित करनी चाहिये, जैसा कि खाड़ी देशों और अफ्रीका में IIT परसिरों के वसितार में देखा जा रहा है ।
- स्थानीय प्रासंगिकता और सांस्कृतिक समावेशन: वदिशी विश्वविद्यालयों को भारतीय शैक्षणिक मूल्यों, भाषाई वविधिता और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करना चाहिये । इसके लिये उन्हें पाठ्यक्रमों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, घरेलू मॉडलों की नकल से बचने और कौशल विकास तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले संदर्भ-वशिष्ट कार्यक्रमों की पेशकश करने की आवश्यकता है ।

नभिकर्ष

वदिशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश की पहल, उच्च शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तनकारी संभावनाएँ लेकर आती है । हालाँकि इनकी सफलता इस बात पर नरिभर करेगी कि वे स्थानीय परस्थितियों के अनुसार स्वयं को कैसे ढालते हैं, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्रदान करते हैं और घरेलू संस्थानों के साथ कसि हद तक सहयोग करते हैं । उचित नयामक संरक्षण और दूरदर्शी नीतियों के साथ यह पहल भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में सशक्त बना सकती है ।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. भारत में वदिशी विश्वविद्यालयों के परसिर स्थापित करने से संबंधित अवसरों एवं चुनौतियों का परीक्षण कीजिये ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]

Q. भारतीय संवधान के नमिनलखिति में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय नकिया
3. पंचम अनुसूची
4. षष्ठ अनुसूची
5. सप्तम अनुसूची

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनयि

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर- (d)

??????

परश्न 1. भारत में डजिटिल पहल ने कसि प्रकार से देश की शकिषा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया है? वसितुत उत्तर दीजयि। (2020)

परश्न 2. जनसंख्या शकिषा के परमुख उद्देश्यों की वविचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर वसितुत परकाश डालयि। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/promoting-foreign-universities-in-india>

